Poonam Shodh Rachna (ISSN 2456-5563)
(A multidisciplinary, peer reviewed and refereed Research Journal)
Vol.2, Issue.6, June 2023, Pc : PSR-2306001

नेपाल के साथ बढती चीन की निकटता एवं भारत की सुरक्षा चिंताए

डा० संजय गौतम
सहायक आचार्य
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
शिवहर्ष किसान पी0जी0 कॉलेज, बस्ती

भारत और नेपाल के मध्य धर्म, भाषा एवं संस्कृति पारस्परिक विश्वास का वातावरण तथा एक दूसरे की भौगोलिक अवस्थिति दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों के आधार हैं। हिमालय के दक्षिणी ढलान एवं भारत के उत्तर में बसा नेपाल, उत्तर में चीन के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। भारत और चीन के मध्य बसा नेपाल एक बफर राज्य के रूप में भारत एवं चीन के मध्य संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है। इस संदर्भ में गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को दो बड़े पत्थरों के बीच खिले हुए पुष्प की संज्ञा दी थी। नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य 1816 में हुए सगौली की संधि के कारण नेपाल, ब्रिटिश भारत के प्रभाव में आ गया। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात दक्षिण एशिया में भू–राजनीति ने अपनी करवटें बदलनी शुरू कर दी। उधर 1949 में नए साम्यवादी चीन का उदय और 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेना भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में नेपाल की महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया। इस संदर्भ में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकसभा में 6 दिसंबर 1958 को दिए अपने भाषण में भारत–नेपाल सौहार्दपूर्ण रिश्ते की बात को स्वीकारते हुए यह कहा कि ‘‘हम नेपाल में किसी भी अप्रिय घटना के कारण अपनी सुरक्षा (भारतीय सुरक्षा) के लिए संकट नहीं खड़ा कर सकते।’’[1]

स्वतंत्र भारत ने नेपाल के साथ रिश्ते और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 31 जुलाई 1950 को शांति एवं मित्रता की संधि का संकल्प लिया, जिसमें भारत की ओर से नेपाल में भारतीय राजदूत 'चंदेश्वर प्रसाद सिंह' एवं नेपाल की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री 'मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा' को पूर्णाधिकारी तौर पर नियुक्ति की गई।[2]

दोनों देशों के मध्य एक खुली सीमा है जिसके माध्यम से दोनों देश के नागरिक निर्बाध रूप से एक दूसरे के यहां यात्राएं कर पाते हैं। साथ ही दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में अपने पारिवारिक रिश्ते, शादी–विवाह भी तय करते हैं इसलिए कहा जाता है कि नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है।

भौगोलिक कारण से नेपाल व्यापार के लिए भी ज्यादातर भारत पर ही निर्भर है क्योंकि चीन और नेपाल के मध्य दुर्गम और व्यापक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन की सुविधा अत्यंत ही सीमित है। भारत सदैव नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियों पर बांध बनाने तथा विकास के अन्य कार्यों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है।[3]

आपदा के समय में सर्वप्रथम भारत ही नेपाल में रहता को बचाव कार्य करने हेतु पहुंचता है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप में अत्यधिक जान माल की क्षति हुई। लगभग 9000 लोग इस भूकंप में मारे गए यहां सर्वप्रथम

भारत ने राहत व बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया तथा नेपाल को 1.54 बिलियन नेपाली रुपया राहत व पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दिया। इसके अगले ही वर्ष 2016 में नेपाल, भारत के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ जिसमें भारत ने दो हिमालय जिले में पुनर्निर्माण हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता लगभग 50000 घरों के निर्माण हेतु हेतु प्रदान की।[4]

नेपाल में बढ़ती चीन की अभिरुचि एवं नेपाल चीन सम्बन्ध

नेपाल इस बात को स्वयं स्वीकार करता है कि उसका चीन के साथ एक प्राचीन रिश्ता है। दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई 1414 किलोमीटर है। नए चीन के अभ्युदय (1949) के बाद 1955 में नेपाल चीन के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। नेपाल चीन के मध्य संबंधों का प्रमुख आधार पंचशील है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य राजनीतिक यात्राएं भी की जाती रही ह। दोनों देशों के मध्य पारस्परिक संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र पर विचार–विमर्श व समीक्षा हेतु द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की भी स्थापना हुई है, जिसका प्रतिनिधित्व चीन के विदेश मंत्रालय के उप मंत्री व नेपाल के विदेश सचिव द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त चीन और नेपाल के मध्य व्यापार, कृषि, पर्यटन तथा अन्य अंतरसरकारी क्षेत्र में समीक्षा व सम्बन्ध सुधार हेतु द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की स्थापना की गई है।

चीन द्वारा नेपाल को तीन श्रेणियां में सहायता प्रदान की जाती है–

1 अनुदान

2 रियायती कर्ज

3 ब्याज मुक्त कर्ज

इसके अलावा चीन द्वारा नेपाल को बुनियादी ढांचे के निर्माण व विकास, मानव संसाधन विकास, औद्योगिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और जल संसाधन हेतु वित्तीय व तकनीकी रूप से वृहद स्तर पर सहयोग किया जाता है।

नेपाली विदेश मंत्री के अनुसार चीन द्वारा नेपाल में चलाई जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

- काठमांडू रिंग सड़क सुधार परियोजना
- ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं और ऊपरी त्रिशूल जल विद्युत परियोजना
- अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय हवाई अड्डा, पोखरा
- नागरिक सेवा अस्पताल का जिर्णोध्दार
- कोडारी क्षेत्र में सड़क व पुल निर्माण संबंधी परियोजना
- सापूबेंसी रस्सुवागढी सड़क का पुनर्निर्माण
- टाटोपानी व रस्सुवागढी फ्रंटियर इंस्पेक्शन स्टेशन परियोजना [5]

इस प्रकार चीन न केवल नेपाल के साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोग बढ़ाकर उसके भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करना चाहता है, अपितु वह दक्षिण एशिया में उभरते महाशक्ति के रूप में भारत को भी नेपाल में प्रभाव विहीन बनाने में जुटा हुआ है।

रेल नेटवर्क को नेपाल से जोड़ने की चीन की तैयारी एवं भारत की सुरक्षाचिंताएं–

चीन, नेपाल को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के संचालन में न केवल आर्थिक मदद देकर उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है अपितु वह रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से भी चीनी रेलवे का विस्तार नेपाल के दक्षिणी सीमा तक करना चाहता है। फिलहाल के लिए वह ट्रांस–हिमालय रेलवे लाइन को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तिब्बत (किंघई) से लेकर नेपाल तक 2008 में 6 रेलवे लाइन चीन द्वारा प्रस्तावित की गई थीं।[6]

पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में लद्दाख तक के भारतीय विभाग का अतिक्रमण के लिए प्रयासरत चीन अब अपना रेल नेटवर्क न केवल ट्रांस–हिमालय क्षेत्र तक सीमित रखेगा, अपितु वह अब भारतीय सीमा से सटे लुंबिनी तक अपना रेलवे लाइन बिछाने पर काम शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्री ने इस पर अपना तर्क देते हुए कहा कि स्थलबद्ध देश नेपाल का अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढेगी तथा पर्यटन, व्यापार व यातायात की भी सुविधा मिलेगी।[7]

चीन के इस कृत्य और रणनीतिक निहितार्थ के कारण न केवल भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी अपितु दक्षिण एशिया में इसका वर्चस्व और बढ़ाने के आसार है।

भारत भी अपनी सुरक्षा चिंताओं व भारत व नेपाल के मध्य संबंधों में प्रगाढ़ता लाने हेतु भारत के बिहार राज्य (जयनगर) से नेपाल के कुर्था तक रेल यातायात सेवा को विस्तारित कर रहा है।यह रेलवे लाइन कुर्था से 17 किलोमीटर और विस्तारित होकर बिजली पूरा तक पहुंच गई है। अब भारत नेपाल की रेल ट्रैक लंबाई 52 किलोमीटर हो गई है। भारत की नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने की इस दूसरे चरण में लगभग 6 अरब रुपए की खर्च आई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के संयुक्त प्रयास से शुरू हुए इस रेल परियोजना से न केवल आर्थिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा अपितु धार्मिक रूप से भी लोगों का रामायण एवं बुद्ध सर्किट में आवागमन आसान हो जाएगा। दोनों देश के नागरिकों के लिए अयोध्या जनकपुर की यात्राएं सुलभ हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा 2018 के दौरान अयोध्या–जनकपुर बस सेवा का भी श्री गणेश हो गया था।

नेपाल व भारत के मध्य रेलवे कनेक्टिविटी ब्रिटिश भारत के समय में 1837 में अंग्रेजों ने व्यापारिक कार्यों हेतु प्रारंभ किया था लेकिन आगे चलकर यह रेलवे लाइन कुछ कारणवश बंद हो गया था।[8]

चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना (OBOR- One Belt One Road) में नेपाल का प्रवेश–

चीन एशिया सहित दुनिया के तमाम अन्य देशों को अपने कर्ज के जाल में फसाना शुरू कर दिया है। जहां भी उसके अपने आर्थिक–रणनीतिक हित दिखाई देते हैं वहां पर वह अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। विकास के नाम पर कथित नव–उपनिवेशवाद के इसी क्रम में चीन ने नेपाल को भी इस जाल में फंसा ही लिया है। मई 2017 में नेपाल–चीन शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राजदूत 'यो होंग' एवं नेपाल के विदेश सचिव 'शंकर दास बैरागी' ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत अब नेपाल की भी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का आधिकारिक

रूप से हिस्सा बन गया। इस दौरान नेपाल के उप प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री कृष्ण बहादुर माहत व विदेश मंत्री प्रकाश शरण माहत भी मौजूद थे।[9]

चीन द्वारा 2013 में शुरू किए गए न्यू सिल्क रुट परियोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत सदस्य देशों को दी जाने वाली कर्ज की शर्तें इतनी कठोर हैं कि इससे बाहर निकलना सामान्य बात नहीं है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके ताजा उदाहरण हैं, और अगर वक्त रहते नेपाल ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि नेपाल की भी आर्थिक हालत बुरी तरह बिगड़ जाएगी अथवा चीन की नई शर्तों को स्वीकार करने के लिए नेपाल तैयार रहे।

भारत के लिए नेपाल का चीन के इस महत्वाकांक्षी परियोजना में प्रवेश का यह कदम चिंतनीय है। चीन को भारत के पड़ोस में रणनीतिक बढ़त[10] हासिल हो जाएगी तथा इसके साथ ही भविष्य की संभावित नए खतरे भी भारत के उत्तर की तरफ से भारतीय सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा देंगे।

भारत एवं नेपाल के मध्य सहयोग के क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक सामरिक व अन्य क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध है। नेपाल आर्थिक रूप से विकास एवं सहयोग हेतु अन्य देशों की अपेक्षा भारत पर अधिकांश रूप से निर्भर है। अधिकांश नेपाली नागरिक जीविकोपार्जन व उच्च शिक्षा हेतु भारत पर ही निर्भर है भारत का नेपाल के साथ अच्छे संबंध सुरक्षा एवं भू राजनीतिक समस्याओं का भारत के पड़ोस में समाधान करने में सुगमता उपलब्ध कराता है। हालांकि कुछ सीमा से संबंधित विवादित मुद्दे भी है जिसमें काला पानी का नाम आता है, जिसकी वजह से भारत–नेपाल रिश्तो में उतार–चढ़ाव का दौर चलता रहता है। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश की सेनाओं के मध्य 'सूर्य किरण' सैन्याभ्यास का भी आयोजन किया जाता है।

दोनों देशों के मध्य बिजली के क्षेत्र में विकास तथा व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहन भी दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं दोनों देशों के मध्य एक दशक के अंदर बिजली निर्यात लगभग 10000 मेगावाट तक बढ़ाने? टर्मिनल्स एवं पाइप लाइनों को विस्तार देने के अतिरिक्त नेपाल के झापा एवं भारत के सिलीगुड़ी के मध्य पैट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने सम्बन्धी समिति भारत–नेपाल रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य रेल संपर्क, जल विद्युत परियोजना, बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजना में सहयोग भी भारत नेपाल द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा।[11]

रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य न केवल 'सूर्यकिरण' सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है इसके अतिरिक्त भारत में गोरखा बटालियन का सहयोग, तथा समय–समय पर रक्षा संबंधी विषय पर बैठकें व वेबीनार का आयोजन भी होता है। इस क्रम में दिसंबर 2020 में भारत को नेपाल के मध्य रक्षा सहयोग पर वेबीनार व एक्सपो का आयोजन किया गया। जिसका मुख्य विषय नेपाल के साथ 'रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना' रखा गया था। यह वेबीनार रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग एस०आई०डी०एस० के माध्यम से आयोजित किया गया था। भारत की ओर से यह वेबीनार सहयोगी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है। इस वेबीनार में 12 भारतीय कंपनियों ने प्रतिभाग किया था।[12]

मूल्यांकन

जिस प्रकार चीन, नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वह भारत के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। नेपाल के साथ भारत अपने विवादों को सुलझाते हुए रिश्ते को बेहतर बनाना, चीनी प्रभाव को संतुलित करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोनों देशों के मध्य काला पानी जैसे सीमा विवाद से तनाव एवं विश्वास का वातावरण सृजित हो सकता है। आत; सीमा विवाद का उच्चस्तरीय व शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा कूटनीति हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना अत्यंत भी महत्वपूर्ण व सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के मध्य सीमा पर गैर–परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का सकारात्मक प्रयास एवं विवाद को भविष्य में रोकना तथा शांति को बढ़ावा देते हुए अन्य समस्याओं के व्यावहारिक समाधान एवं प्रभावी सीमा प्रबंधन दोनों देशों के मध्य रिश्ते को बेहतर बना सकता है।

नेपाल में बढ़ते चीन के प्रभाव को देखते हुए नेपाल के प्रति भारत को एक दूरदर्शी नीति बनानी होगी। नेपाल में जिस प्रकार चीन अपना प्रभाव वृद्धि में लगा हुआ है वह भारत के हित में नहीं है तथा भविष्य की संभावित नए खतरे और नई सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न कर सकती है।

संदर्भ सूची ; References

1. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 6 दिसंबर 1958 को भारतीय पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण।

2- Ministry Of Eûternal Affairs, Government Of India, 31 July 1950, Kathmandu

or See

https://mea-gov-in/bilateral&documents-htm\dtl/6295/Treaty+of+Peace+and+Friendship

3. Meena, Dr. Rakesh Kumar, Indian Council of World Affairs, Sapru House,New Delhi, 9 July -2015

or see

https://icwa-in/show_content-php\lang¾1&level¾3&ls_id¾558&lid¾429

4. the hindu , 14 September, 2020

Or see

https://www-google-com/amp/s/www-thehindu-com/news/international/india&provides&154&billion&rupees&to&nepal&as&post&earthquake&assistance&indian&embassy/article32687027-ece/amp/

5. Ministry of Foreign Affairs, Government Of Nepal, Singh, Durbar, Kathmandu (Nepal)

or See

https://mofa-gov-np/nepal&china&relations/

6. Jaiswal, Pramod, Senior Fellow, Institute Of Peace And Conflict Studies, (IPCS), 6 October- 2014
7. नवभारत टाइम्स, 15 दिसंबर–2021

or See

https://www-google-com/amp/s/navbharattimes-indiatimes-com/world/asian&countries/tibet&railway&china&to&build&railway&line&road&till&lumbini&in&nepal&move&to&worry&india/amp_articleshow/88289454-cms

8. Jagran, Epaper, 15 July-2023

or see

https://www-google-com/amp/s/www-jagran-com/lite/news/national&india&nepal&railway&network&railway&is&becoming&the&link&of&india&nepal&relations&rail&service&will&start&from&sunday&on&jaynagar&janakpur&eÛtended&rail&line&23472332-html

9. The Kathmandu Post, Sun,10 September-2023

or See

https://kathmandupost-com/national/2017/05/12/nepal&china&sign&framework&deal&on&obor

10. Jha, Harivansh, Observer Research Foundation, New Delhi, 21 Jun- 2017

Or see

https://www-orfonline-org/hindi/research/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2&%e0%a4%b5%e0%a4%a8&%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%9f&%e0%a4%b5%e0%a4%a8&%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1/\amp

11. The Hindu, Epaper 9 June- 2023

or See

12. Press Information Beuro, New Delhi (2020)

or See

https://pib-gov-in/PressReleasePage-aspÛ\PRID¾1682604

13. https://www-google-com/amp/s/www-orfonline-org/hindi/research/finding&an&end&to&border&disputes&the&india&nepal&imperative/